भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1802

उत्तर देने की तारीख 2 मार्च, 2020

सोमवार, 12 फाल्गुन, 1941 (शक)

रोजगार अवसरों संबंधी सूचना

1802. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास मैट्रिक, ग्रैजुएशन, पोस्ट-ग्रैजुएशन तथा अन्य कौशल आधरित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों को उपलब्ध रोजगार अवसरों के बारे में सूचना प्रदान करने का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो इस तंत्र के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2015 के पश्चात इन पाठ्यक्रमों में वर्ष-वार कितने छात्र नामांकित हुए;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास इस प्रकार का तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय केरियर सेवा (एनसीएस) नामक एक मिशन मोड परियोजना प्रारंभ की थी। एनसीएस एक वन-स्टॉप समाधान है, जो भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के रोजगार और केरियर संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह नौकरी खोजने वालों और नियोजकों, प्रशिक्षण और केरियर मार्गदर्शन चाहने वाले उम्मीदवारों, प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों और केरियर परामर्श के बीच के अंतर को पाटने का कार्य करती है। एनसीएस परियोजना अपने तीन अनिवार्य स्तम्भों अर्थात आईसीटी आधारित सुव्यवस्थित पोर्टल जो एनसीएस पोर्टल है, देशव्यापी आदर्श केरियर केंद्र और रोजगार कार्यालयों के जरिए सभी राज्यों के साथ अंतर संबद्धता के माध्यम से इस देश के लोगों तक पहुंच है। डिजिटल केंद्रीयकृत पोर्टल नौकरी की खोज, जॉब मैचिंग, समृद्ध केरियर विषय-वस्तु, केरियर परामर्श, जॉब मेलों संबंधी सूचना सहित केरियर संबंधी सेवाओं, घरों के लिए ड्राईवरों, प्लम्बरों आदि जैसे स्थानी सेवा प्रदाताओं की सेवाओं और अन्य कुशल कामगारों से संबंधित बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है। यह पोर्टल नौकरी खोजने वालों, नियोजकों, कौशल प्रदाताओं, केरियर परामर्शकों, स्थानीय सेवा प्रदाताओं (एलएसपी), केरियर केंद्रों प्लेसमेंट संगठनों, घरों (एलएसपी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए) और सरकारी विभागों का पंजीकरण करता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भी श्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित कर रहा है जिससे भावी नियोजक एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित कुशल कार्मिकों का डाटाबेस प्राप्त कर सकेंगे ताकि नौकरी खोजने वालों और नियोजकों के मिलने का एक धरातल तैयार होगा।

यह मंत्रालय एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 का कार्यान्वयन कर रहा है। नामांकित और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का वर्ष-वार ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	नामांकित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या
2016-17	5.97	281
2017-18	24.28	4,53,003
2018-19	28.59	7,04,215
2019-20	23.85	5,04,462

****